जमीन है और हम लोग जो यहां सदस्य हैं, उन को 210 गज जमीन भी नहीं मिलती। आप काआपरेटिव सोसाइटी बनने नहीं देते और मंत्री जी मुलाकात करने से घबराते हैं। और तो और लेफ्टीनेंट गवर्नर से भी संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है। अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पार्लियामेंट के मेम्बरों को किसी बावेजा कमेटी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: आप सीधा सवाल पूछिये कि क्या कमेटी हटा कर दूसरी कमेटी बनायी जाएगी ?

श्री डी० पी० यादव : मैं जानना चाहता हूं कि क्या बावेजा कमेटी को हटा कर कोई इसके लिए दूसरी कमेटी मेम्बर आफ पार्लियामेंट की बनायेंगे या नहीं ?

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: "Baweja Gaweja". I do not know. The Baweja Committee submitted their recommendations to the previous Government, the Janta Government, and they accepted the recommendations of the Committee. Even according to the Committee, he has classified certain sections to be brought under reservation....

MR SPEAKER : Whether you prepared to appoint a new parliamentary committee.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: As regards constituting cooperative societies for getting land for MPs and that is what our friends has been trying to impress open the Government, this is a matter to be considered. It is a suggestions that has been given. The Government will certainly consider a reasonable suggestions made by hon. Members so that they may not be put to difficulties in the matter of accommodation.

अध्यक्ष महोदय: आप तो 210 गज जमीन की बात करते हैं, मैं तो समझता हूं कि दो गज जमीन भी न मिली...

श्री हरीश कुमार गंगवार : यह जो एम० पीज के लिए रिजर्वेशन थी और लिस्ट बनी थी उन्होंने पैसा जमा कराया था, 15-15 हजार रूपये जमा कराये थे तो अब स्कीम कैंसिल हो गयी तो उस पैसे का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय: आप इसके लिए दूसरा सवाल दीजिए।

देसी घी के मूल्य में वृद्धि

309. **श्री तारिक अनवर:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में "देशी" घी के मूल्यों में अचानक वृद्धि के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार ने अपने "देशी" घी (डी० एम० एस० घी) की कीमत में वृद्धि की है, और ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इसकी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाये है और इस बारे मे सरकार द्वारा और आगे क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI R. V. SWAMINATHAN) : (a) The production and marketing of desi ghee is largely in the hands of private trade. It is not subject to price control. The increase in prices of desi ghee appears to have been influenced by the seasonal fall in the availability of raw-milk in summer months and by the behaviour of the prices of edible oils.

(b) Yes, Sir. However, the DMS has an insignificant share in the desi ghee market and its price is still the lowest as compared to the price of other brands of ghee.

(c) In view of answers to parts (a) and (b) this doe not arise.

श्री तारिक अनवर : अध्यक्ष महोदय, आज यह बात चिंताजनक है कि कोई भी उत्पादक जब चाहे अपने उत्पादन का मूल्य बढ़ा देता है। यह नीति केवल घी या तेल अथवा किसी एक चीज को नहीं हर सामान को है। उस के बाद सरकार को उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर उद्योगपतियों से उसके मूल्य को कम करने के लिए बात करना पड़ता है, जो कि अनुचित है। होना तो यह चाहिए कि कोई भी उद्योगपति या उत्पादक अपने यहां उत्पादित माल के मूल्यों में वृद्धि करना चाहता है तो उसे पहले सरकार से अनुमति प्राप्त करनी चाहिए और उसके लिए पर्याप्त कारण भी देना चाहिए। जब तक सरकार की स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक उसे मूल्य बढ़ाने का अधिकार नहीं होना चाहिए अन्यथा मार्केट मूल्यों पर सरकार को नियंत्रण करना संभव नहीं होगा। क्या सरकार ऐसे कदम उठाने जा रही है कि वे अनुमति ले कर ही दाम बढ़ाएं ?

SHRI R.V. SWAMINATHAN: So far as the price of the desi ghee in the private trade is concerned theyhave their own way of increasing the price. So far as the Government dairy is concerned, the DMS, we are having a controlled price and our price is the lowest as compared to the price of ghee in the market.

श्री तारिक अनवर : अध्यक्ष महोदय मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मेरा प्रश्न यह था कि प्राइवेट सेक्टर जब दाम बढ़ाते हैं तो इस से पहले सरकार की अनुमति लेते हैं या नहीं लेते हैं ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION AND IRRIGATION AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIREDNRA SINGH) : If the suggestion of the Hon. Member is that Government should control the price of Desi Ghee produced by cattle-owners, I have to say that we are not considering anything like that. We do not want to impose any controls on cattle-owners for fixing a price for their procuce.

श्री तारिक अनवर : आप उस पर कंट्रोल नहीं करते हैं, लेकिन जो सरकारी नियंत्रण में घी का उत्पादन हो रहा है है, उसके दाम पिछले तीन महीने में ही 10 रुपये बढ़ गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले एक वर्ष में उसके दाम में कितना बढ़ोतरी की गई है ?

RAO BIRENDRA SINGH : I would very respectfully suggest that to understand the whole economics of production of desi Ghee in farmers' houses, the Hon. Member should keep a cow or a buffalo. Then he will know the cost of production of Desi Ghee.

श्री आर० एन० राकेश : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आज देश में ऐसी कोई चीज नहीं है, यहां तक कि पेयजल भी शुद्ध नहीं मिलता है, क्या इसीलिए दिल्ली मिल्क स्कीम के डिब्बे से शुद्ध शब्द हटा दिया गया है। पहले उस पर "शुद्ध घी" लिखा रहता था और अब सिर्फ "घी" लिखा होता है।

राव वीरेन्द्र सिंह : जनाब शुद्ध का कुछ भी मतलब लिया जा सकता है। शुद्ध की डेफीनेशन क्या है, किस हद तक क्या चीज शुद्ध होती है— यह मैं बताने में असमर्थ हूं।

श्री आर० एन० राकेश : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, शुद्ध शब्द क्यों हटाया गया ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो अंडर-स्टुड है ।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : मैं शुद्धता के बारे में न पूछते हुए यह पूछना चाहती हूं कि घी इतना मंहगा हो गया है कि हर आदमी उसको नहीं खरीद सकता, उसके बदले लोग बटर-आयल का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग भी उसका इस्तेमाल करते हैं। पिछले दिनों उसके दाम भी 17 से 20 रुपये हो गए । मैं पूछना चाहती हूं कि यह बटर-आयल हमको किस भाव से मिलता है और यह गिफ्ट के तौर पर जब आता है इसकी कीमत इतनी क्यों है, इसके क्या कारण हैं और इससे हमारे किसानों को क्या फायदा है।

राव वीरेन्द्र सिंह : बटर-आयल हमारे फ्लड प्रोग्राम के तहत गिफ्ट के तौर पर आता है, बाहर के मुल्कों से। आम तौर पर वह बेचने के लिए नहीं है कि उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अन्तर्गत रखा जा सके। इस से जो फायदा होता है उसको दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के काम में लिया जाता है। इस के लिए पहले हमारा फ्लड वन प्रोग्राम चला, उस के बाद अब फ्लड-टू प्रोग्राम चल रहा है। यह सारा पैसा इस के लिए काम में लाते हैं।

Setting up of central soil reaserch Institute

*310. SHRI S. B. SIDNAL :
SHRI LAKSHMAN MALLICK :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn towards the demand for setting up of a Central Soil Research Institute to promote effective use of soil and establish a linkage between the proposed institute and the farmers ; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION IRRIGATION AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH) : (a) Yes Sir, the Indian Council of Agricultural Research has formulated a Sixth Plan proposal for establishing an Indian Institute of Soil Research. The proposal has been cleared by the Planning Commission and is being processed further for clearance by the Finance Department.

(b) Primary objective of the Institute would be to carry out basic research on soils. The Institute's plan envisages five main laboratories viz. Colloid Chemistry, Soil Physics, Soil Chemistry. Soil Microbiology and Soil Organic Matter and Recycling. An initial outlay of Rs. 90 lakhs for four years of Sixth Plan period has been provided to establish the nucleus set up which will grow in due course. The site of the Institute would be decided on the basis of the expert advice.

SHRI S. B. SIDNAL : The hon. Minister has not answered the last part of my question, that is, about establishing a linkage between the proposed Institute and the farmers directly. Secondly, in his view, who are tge experts whose opinion will be sought on site selection ?

RAO BIRENDRA SINGH : The question of site selection has not yet been taken up. With regard to the other question of the hon. Member—he wanted to know about linkage between the Central Soil Research Institute and the farmers—the Institute has not yet been set up; so, the question of linkage with farmers at present does not arise. We have already several other Institutes. In fact, we have five national Institutes on soil research already working in the field : one of